



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022026-270032
CG-DL-E-11022026-270032

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 631]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2026/माघ 20, 1947

No. 631]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2026/MAGHA 20, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2026

का.आ. 665(अ).—पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सहायिकियों, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को दूर करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है ;

और, भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सरकार कहा गया है) में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (जिसे इसमें पश्चात्, यथास्थिति, उक्त मंत्रालय या उक्त विभाग कहा गया है) "राह-वीर (पूर्ववर्ती गुड समारटियन)" (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त योजना कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है ;

और, उक्त योजना के अधीन राह-वीर (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त लाभार्थी कहा गया है) को 25,000/- रुपये का पुरस्कार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त लाभ कहा गया है) दिया जाता है और उसके संबंध में निर्देश और दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ;

और, उक्त योजना के लिए व्यय भारत की संचित निधि में से उपगत किया जाता है ;

और, उक्त मंत्रालय इच्छुक है कि उक्त सरकार, उक्त लाभ की प्राप्ति के लिए एक लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए, यह अपेक्षा करती है कि ऐसा लाभार्थी प्रमाणीकरण से गुजरे, या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करे या किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे कोई आधार संख्या नहीं दी गई है, नामांकन के लिए आवेदन करे :

अतः, अब, भारत सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

1. (1) उक्त योजना के अधीन उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी व्यक्ति को प्रमाणीकरण करवाना होगा, या आधार संख्या होने का सबूत देना होगा।

(2) उस दशा में, जब ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दी गई है, उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा :

परंतु यदि वह व्यक्ति कोई बालक है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या कानूनी संरक्षक की सहमति से किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे लाभार्थियों का, जिसका अभी नामांकन नहीं किया गया है, का नामांकन हो या समुचित उपायों के माध्यम से, जिनमें रजिस्ट्रार के साथ समन्वय और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्र स्थापित करना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराना सम्मिलित है, उनके आधार विवरण को अद्यतन करेगा :

परंतु ऐसे समय तक, जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या नहीं दी गई है, वह उक्त लाभ को, जिसका वह हकदार है, प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेजों को, जो प्रस्तुतीकरण के समय विधिमान्य हैं, प्रस्तुत करके, या, उस मामले में, जब ऐसी पहचान के लिए उक्त मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर, सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने में सहायता करता है, ऐसे दस्तावेजों को तैयार करने या उनके रखरखाव से संबंधित प्राधिकारियों के डेटाबेस से ऐसे दस्तावेजों की सामग्री को प्रमाणित करने वाली जानकारी को, ऐसा प्राप्त करने के लिए उसकी सहमति देते हुए, अपनी पहचान स्थापित कर सकेगा, अर्थात् :—

18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक के लिए, जिसको आधार संख्या नहीं दी गई है :—

(क) लाभार्थी के नामांकन प्रक्रिया से गुजरने की, नामांकन केंद्र पर, प्रचालक द्वारा उपलब्ध कराई गई, पावती, जिसमें नामांकन आईडी (ईआईडी) सम्मिलित है ; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, जो इस बात के प्रमाणित करे कि लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु का बालक है, अर्थात् :—

(i) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन, लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म के रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से यथा उद्धृत, जन्म प्रमाण पत्र ;

(ii) भारतीय पासपोर्ट ;

(iii) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी, मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा के अंकों का प्रमाण पत्र या विवरण ;

(iv) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि के उल्लंघन वाले बालक के संबंध में, जो ऐसे बाल देखरेख संस्था द्वारा रखा गया है, जो संबंधित राज्य सरकार के पास, उसके द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का 26) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत है, ऐसी संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्म की तारीख निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र ; या

(v) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(I) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक है, तो भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड ;

(II) यदि वह एक तिब्बती शरणार्थी है, तो एक विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट ;

(IV) यदि वह भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा ; या

(ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी का फोटो हो, जो माता-पिता या कानूनी संरक्षक के साथ उसके संबंध को प्रमाणित करे, अर्थात् :—

(i) राशन कार्ड ;

(ii) राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अनिम्न, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजस्व अधिकारी है, द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र ;

(iii) किसी सरकारी इकाई या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र ;

(iv) भारतीय पासपोर्ट ;

(v) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी, मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा के अंकों का प्रमाण पत्र या विवरण ;

(vi) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि के उल्लंघन वाले बालक के संबंध में, जो ऐसे बाल देखरेख संस्था द्वारा रखा गया है, जो संबंधित राज्य सरकार के पास, उसके द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का 26) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत है, ऐसी संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्म की तारीख निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र ; या

(vii) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(I) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक है, तो भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड ;

(II) यदि वह एक तिब्बती शरणार्थी है, तो एक विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट ;

(IV) यदि वह भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा ; या

(viii) किसी लाभार्थी के संबंध में, जिसका विधिक संरक्षक है, विधिक संरक्षण के प्रमाण वाला दत्तक आदेश या अन्य दस्तावेज, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का 26), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है ; या

(ix) कोई अन्य दस्तावेज, जो उक्त मंत्रालय विनिर्दिष्ट करे।

18 वर्ष या अधिक आयु के ऐसे लाभार्थी के लिए, जिसको आधार संख्या नहीं दी गई है:—

(क) लाभार्थी के नामांकन प्रक्रिया से गुजरने की, नामांकन केंद्र पर, प्रचालक द्वारा उपलब्ध कराई गई, पावती, जिसमें नामांकन आईडी (ईआईडी) सम्मिलित है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, जिसमें लाभार्थी का फोटो हो, अर्थात्:—

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड ;

(ii) राशन कार्ड ;

(iii) राज्य सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से अनिम्न, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजस्व अधिकारी है, द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र ;

(iv) किसी सरकारी इकाई या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र ;

(v) भारतीय पासपोर्ट ;

(vi) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी, मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा के अंकों का प्रमाण पत्र या विवरण ;

(vii) किसी सरकारी इकाई या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज ;

(viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, या भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) पत्र ;

(ix) भारत में जारी चालन अनुज्ञप्ति ;

(x) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि के उल्लंघन वाले बालक के संबंध में, जो ऐसे बाल देखरेख संस्था द्वारा रखा गया है, जो संबंधित राज्य सरकार के पास, उसके द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का 26) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत है, ऐसी संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्म की तारीख निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र ; या

(xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(I) यदि वह भारत का प्रवासी नागरिक कार्डधारक है, तो भारत का प्रवासी नागरिक कार्ड ;

(II) यदि वह एक तिब्बती शरणार्थी है, तो एक विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट ;

(IV) यदि वह भारत के विदेशी नागरिक कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत का दीर्घकालिक वीजा ; या

(xii) किसी लाभार्थी के संबंध में, जिसका विधिक संरक्षक है, विधिक संरक्षण के प्रमाण वाला दत्तक आदेश या अन्य दस्तावेज, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2015 का 26), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियमों और विनियमों के अधीन किसी न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है; या

(xiii) कोई अन्य दस्तावेज, जो उक्त मंत्रालय विनिर्दिष्ट करे।

(4) उक्त मंत्रालय द्वारा इस निमित्त पदाभिहित कोई अधिकारी, खंड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी अंतर्वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना के संबंध में जांच करेगा,—

(क) यह पुष्टि करने के लिए कि नामांकन पहचान विधिमान्य है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं है, myAadhaar पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर नामांकन पहचान प्रस्तुत करके नामांकन अनुरोध की प्रास्थिति की; और

(ख) अन्य दस्तावेज, और इस प्रयोजन के लिए, किसी ऐसी सरकारी इकाई या किसी प्राधिकारी की, जो ऐसे दस्तावेजों में निहित सूचना की तैयारी या रखरखाव से संबंधित हैं, सहायता ले सकेगा और उनके साथ प्रस्तुत सूचना सांझा कर सकेगा।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभों का फायदा आसानी से उठाने में सक्षम बनाने के लिए, मंत्रालय, मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, जिससे लाभार्थियों को उक्त स्कीम के अधीन आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. जहां किसी भी बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण (अर्थात्, चेहरे की छवि, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से लाभार्थी के आधार संख्या का प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता, जैसे किसी भी कारण से विफल हो जाता है, वहां, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) यदि कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण विधि सफल नहीं होती है, तो कोई अन्य बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण विधि या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण, जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, की पेशकश की जाएगी;

(ख) ऐसे मामलों में, जहां बायोमेट्रिक-आधारित या वन-टाइम पिन-आधारित प्रमाणीकरण के तरीके संभव नहीं हैं, उक्त योजना के अधीन लाभ, यथास्थिति, आधार सिक्योर क्लिक रिस्पांस (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का ऑफलाइन सत्यापन करके आधार संख्या की प्रामाणिकता स्थापित करने के पश्चात्, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जा सकता है :—

(i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात्, आधार संख्या बनाने पर आधार संख्याधारक को जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात्, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र की पासवर्ड-संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या इसके एमआधार ऐप का सुलभ उपयोग करके), आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता स्थापित होने के बाद।

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है), इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी प्रामाणिकता स्थापित होने के पश्चात्, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार।

4. उपर्युक्त अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी,—

(क) उक्त योजना के अधीन किसी बालक को निम्नलिखित लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा,—

(i) पहचान के सत्यापन से गुजरने या आधार संख्या के होने का प्रमाण प्रस्तुत करने में विफलता की स्थिति में ; या

(ii) नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में जहां उसे आधार संख्या आवंटित नहीं किया गया है ; और

(ख) उक्त योजना के अधीन लाभ ऐसे बालक को उसकी पहचान सत्यापित करके और पैरा 1 के खंड (3) के परंतुक में निर्दिष्ट तरीके से उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके दिया जाएगा ; और

(ग) जहां खंड (ख) के अधीन लाभ दिया जाता है, वहां उसी के संबंध में एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसकी समय-समय पर मंत्रालय द्वारा समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी ।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के *वास्तविक* लाभार्थी उक्त योजना के अधीन उन्हें मिलने वाले लाभ से वंचित न हों, मंत्रालय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी, दिनांक 19 दिसंबर, 2017 (<https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध) में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा ।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. आरटी-25035/46/2022-आरएस]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2026

S.O. 665(E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Ministry of Road Transport and Highways (hereinafter referred to as the said Ministry or the said Department, as the case may be) in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering “Rah-Veer (erstwhile Good Samaritan) (hereinafter referred to as the said scheme):

And whereas an award of ₹25,000/- (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the Rah-Veer (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof:

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India:

And whereas the said Ministry is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment:

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Ministry shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said Ministry for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID); and
- (b) any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely:—
 - (i) Certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;
 - (ii) Indian passport;
 - (iii) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
 - (iv) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act (2 of 2016), 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
 - (v) In respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (c) any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely:—
 - (i) Ration card;

- (ii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
- (iii) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
- (iv) Indian passport;
- (v) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
- (vi) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
- (vii) In respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (viii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (ix) Any other document as the said Ministry may specify.

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

- (a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID; and
- (b) any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—
 - (i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
 - (ii) Ration card;
 - (iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
 - (iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
 - (v) Indian passport;
 - (vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;

- (vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
 - (viii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;
 - (ix) Driving licence issued in India;
 - (x) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
 - (xi) In respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
 - (xii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
 - (xiii) Any other document as the said Ministry may specify:
- (4) An officer designated by the said Ministry in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—
- (a) the status of the enrolment request by submitting the Enrolment ID on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the Enrolment ID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
 - (b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any

reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b) In cases where biometric-based or one-time pin-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of India on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:

(i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.*, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.*, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of Unique Identification Authority of India or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of Unique Identification Authority of India or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of India on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of Unique Identification Authority of India.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—

(a) benefit under the said scheme shall not be denied to a child—

(i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or

(ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and

(b) benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and

(c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Ministry.

5. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Ministry shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).

6. This notification shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. RT-25035/46/2022-RS]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.